फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 130 प्रभात जयपुर, गुरूवार 11 दिसम्बर, 2025 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

Gyaraspur Ki Apsara In A Store Room With Bars?

In a barred antechamber to the right of the curator's tube-lit and laminate-walled sarkari office rests a millennium-old nature spirit or yakshi, identified as a 'salabhanjika'

'Zia' Fitted 'Nisha'

From Headlines to Melody : How a Newspaper Inspired R. D. Burman's 'Nisha' in Sanam Teri Kasam

राहुल ने गृह मंत्री शाह से पूछा, ''चुनाव आयुक्त'' को सरकार ने सभी कानूनी कार्यवाही व दंड देने से मुक्ति क्यों दी है?

प्रत्युत्तर में अमित शाह ने पूछा, ''इंदिरा गांधी ने अपने आपको सभी कानूनी कार्यवाही और दण्ड से मुक्ति क्यों प्रदान की थी, जब न्यायालय ने उन पर गैर वाजिब तरीके से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था''

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 दिसंबर। लोकसभा में एसआईआर पर हुई बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद, राहुल गांधी ने तीखी टिप्पणी की।

गृह मंत्री के जवाब से असंतुष्ट संयुक्त विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ठीक मोदी की तरह, गृह मंत्री ने भी कांग्रेस पर हमला करने में ज़्यादा समय गंवाया, बजाय इसके कि एसआईआर के उन विवादित पहलुओं पर स्पष्टीकरण देते, जिन पर राजनीतिक दल लगातार सवाल उठा रहे हैं।

शाह के जवाब के बाद राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री उनके द्वारा उठाए गए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- एक वरिष्ठ नेता ने लोकसभा में हुई इस नोक-झोंक पर टिप्पणी की कि शाह चुनाव आयुक्त से तुलना कर रहे हैं तथा यह भी सच है कि अपने को ''इम्युनिटी'' प्रदान करने के बाद, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थीं।
- राहुल गांधी ने नोक-झोंक के बाद दावा किया कि अमित शाह नोक-झोंक के दौरान रक्षात्मक मुद्रा में थे।
- राहुल गांधी ने तीन सवाल उठाए थे। पहला सवाल था, उन्हें वोटर लिस्ट का, मशीन द्वारा पढ़ा जा सके, ऐसा प्रिंटआउट क्यों नहीं दिया गया।
- दूसरा सवाल था, ईवीएम के काम करने के तरीके का ''पारदर्शी'' ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा।
- तीसरा सवाल था, चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्यों अलग किया गया।
- कांग्रेस की रणनीति है कि राहुल गांधी के सवालों का जो भी जवाब अमित शाह ने लोकसभा में दिया है, उसी को कमोबेश कांग्रेसाध्यक्ष खड़गे अगले दिन राज्यसभा में उठायेंगे।

थरुर ने सावरकर अवॉर्ड ठुकराया

तिरुवनंतपुरम, 10 दिसंबर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार को वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 को ठुकराते हुए कहा कि उन्हें हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (एचआरडीएस इंडिया) द्वारा घोषित इस सम्मान के बारे में कभी सूचित ही नहीं किया गया था।

इससे पहले एनजीओ ने नयी दिल्ली में उद्घाटन पुरस्कार समारोह के लिए चयनित छह हस्तियों में थारूर का

- थरुर ने कहा, उन्हें अवॉर्ड की जानकारी तब मिली जब वे केरल में थे, उन्हें अवॉर्ड की प्रकृति व अवॉर्ड देने वाले संगठन के बारे में कुछ भी पता नहीं है।

नाम भी शामिल किया था, इस समारोह में कथित रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे।

थरूर ने कहा कि उन्हें इस घोषणा के बारे में मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से ही पता चला जब वह स्थानीय निकाय चुनावों में अपना वोट डालने के लिए केरल में थे।

थरूर ने लिखा कि उन्हें पुरस्कार की प्रकृति, इसे प्रदान करने वाले संगठन या किसी भी प्रासंगिक विवरण के बारे में जानकारी नहीं थी और इसलिए कार्यक्रम में भाग लेने या सम्मान स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

एनडीए गठबंधन की घटक तेलगु देशम पार्टी काफी क्षुब्ध है, प्र.मंत्री व गृह मंत्री से

मुद्दा है, तेलगु देशम के कोटे से नियुक्त युवा नागरिक उड्डयन मंत्री को भाजपा प्र.मंत्री मोदी व गृह मंत्री द्वारा निहत्था छोड़ देना, इंडिगो एयरलाइन्स के मसले पर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर। इंडिगो एयरलाइंस संकट को संभालने के तरीके को लेकर तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) और भाजपा के बीच बढ़ती नाराज़गी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में एक नई खलबली पैदा कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के करीबी वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, उन्हें यह बात बहुत खली है कि भारत के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को ''अनावश्यक राजनीतिक अपमान'' झेलना पड़ा।

टीडीपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि व्यापक उड़ान व्यवधानों के कारण पैदा हुए संकट के दौरान राम मोहन नायडू की कड़ी आलोचना से पार्टी हैरान रह गई। एक वरिष्ठ टीडीपी सांसद ने खुलकर कहा कि यह संकट ''हद से ज्यादा एकाधिकार वाली विमानन व्यवस्था'' का नतीजा है, जो कथित तौर पर इंडिगो के पक्ष में है और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- तेलगु देशम की शिकायत है कि जब भी कोई भारी संकट का समय प्रस्तुत हुआ है, चाहे पहलगाम का आतंकी हमला हो या बालासोर की भारी ट्रेन दुर्घटना या लाल किले पर आतंकी बम विस्फोट, प्र.मंत्री, गृह मंत्री स्वयं आगे आए हैं, सरकार का पक्ष रखने।
- पर, इस बार इंडिगो एयरलाइन्स के देश व्यापी झमेले में दोनों नेताओं ने एकदम कुछ नहीं बोला।
- तथा सबसे युवा कैबिनेट मंत्री राम मोहन नायडू, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही उड्डयन मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है, के पक्ष में भाजपा का कोई नेता खड़ा नहीं हुआ और युवा मंत्री को सारी आलोचना व निंदा स्वयं वहन करनी पड़ी।
- अन्ततोगत्वा तेलगु देशम पार्टी के नेता व मु.मंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्वयं यह कहना पड़ा, ''जिस गंभीरता, पारदर्शिता से व बिना विचलित हुए युवा उड्डयन मंत्री इस संकट से निपटे वह प्रशंसनीय है।''
- तेलगु देशम व भाजपा के बीच यह भावात्मक दूरी एनडीए सरकार के लिए शुभ समाचार नहीं है।

'टैरिफ का कारण रूसी तेल नहीं, सीज़फायर में ट्रंप की भूमिका को नकारना था'

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने युनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिख़ में एक कार्यक्रम के दौरान यह दावा किया

-सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर। एक चौंकाने वाले खुलासे में, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने का कारण मोदी सरकार द्वारा डॉनल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान युद्धविराम में मध्यस्थता के दावे को खारिज करना था, न कि भारत का रूस से तेल आयात करना।

ज़्यूरिख विश्वविद्यालय में बोलते हुए, राजन ने कहा: ''रूस का तेल मुद्दा नहीं था... मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दा ज्यादा व्यक्तित्वों से संबंधित था, खासकर वाइट हाउस में एक व्यक्ति से और ट्रंप द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने का श्रेय लेने के बाद भारत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को उन्होंने कैसे लिया... इससे सम्बधित था। पाकिस्तान ने इसे सही तरीके से

- राजन के दावे से एक भारी ऑनलाइन बहस छिड़ गई है। मोदी समर्थकों का कहना है कि भारत सरकार ने ट्रंप के दबाव के बजाय राष्ट्रीय हितों को तवज्जो दी।
- राजन ने कहा कि ट्रंप के दावों पर पाकिस्तान सही खेला, उसने न केवल ट्रंप का दावा स्वीकार किया, बल्कि नोबेल के लिए ट्रंप का नाम भी आगे बढ़ाया।

खेला... और कहा कि यह सब ट्रंप की वजह से था।''

पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा, ''भारत ने यह दलील देने की कोशिश की थी कि दोनों देशों ने ट्रंप के बिना समझौता किया था... सच शायद बीच में कहीं है... लेकिन इसके परिणामस्वरूप भारत को 50 प्रतिशत टैरिफ मिला, और पाकिस्तान को मात्र 19 प्रतिशत। मुझे समझ में आता है कि स्विट्ज़रलैंड में आपके नेता ने ट्रंप को शुल्क के बारे में समझाने की कोशिश की थी, और यह अच्छा नहीं हुआ... तो हम नहीं जानते कि भारत और अमेरिका के बीच वास्तव में क्या हुआ, लेकिन उम्मीद है कि लंबी अवधि में सभी पक्षों पर समझदारी का पालन होगा और हम सभी उचित डील तक पहुंचेंगे।''

अगस्त में, वॉशिंगटन ने भारत द्वारा रुस से तेल खरीदने के नाम पर भारतीय वस्तुओं पर व्यापार शुल्क को 50 प्रतिशत तक दोगुना कर दिया था।

अक्टूबर में, ट्रंप ने दावा किया था कि मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वचन दिया था।

जब भारत के इस बयान के बारे में पूछा गया कि उसे मोदी और ट्रंप के बीच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बैल्जियम से मेहुल चोकसी का प्रत्यार्पण सन्निकट

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर। अधिकारियों ने बताया कि बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट, ''कोर्ट ऑफ कैसेशन'', ने मंगलवार को भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की उस अपील

- 1500 करोड़ रूपए के पीएनबी घोटाले में वांछित भगोड़े मेहुल चोकसी की प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर अपील बैल्जियम कोर्ट ने ठुकरा दी।

को खारिज कर दिया, जिसमें उसने पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले के मामले में भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती दी थी।

चोकसी जनवरी 2018 में,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप की प्रशासनिक निर्णय लेने की क्षमता पर पुनः चिंता जताई जाने लगी है

राष्ट्रपति ट्रंप के भतीजे फ्रेड ट्रंप तृतीय द्वारा अपने परिवार के बारे में हाल ही में प्रकाशित पुस्तक से इस चर्चा को और मजबूती मिल रही है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के व्यवहार और फैसले लेने के तरीके को लेकर चिंताएँ एक बार फिर से सामने आई हैं। हाल के दिनों में उनके कई अनियमित सार्वजनिक बयानों और उनके ही परिवार के कुछ सदस्यों में बढ़ती बेचैनी ने इस चिंता को हवा दी है। राजनीतिक आलोचक लंबे समय से ट्रंप पर, जल्दबाज़ी में फैसले लेने और बढ़ा-चढ़ाकर बोलने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन हाल की घटनाओं ने इस बात पर व्यापक बहस छेड़ दी है कि क्या उनका करीबी ग्रुप ऐसे व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है, जो उनके दूसरे कार्यकाल में शासन को कमज़ोर कर सकता है।

ट्रंप के आलोचक उन मौकों की ओर इशारा करते हैं, जब चुनाव प्रचार के दौरान या पद पर रहते हुए उन्होंने

- पुस्तक के अनुसार, ट्रंप परिवार में बढ़ती उम्र के साथ परिवार के बुजुर्गों में समझने, याद रखने और सोचने जैसी संज्ञानात्मक क्रियाओं में दिक्कत आने लगती है।
- किताब के अनुसार, लेखक के पितामह फ्रेड ट्रंप सीनियर कई साल तक अलज़ाइमर बीमारी के साथ जिए थे तथा परिवार के कई अन्य वृद्ध इन बीमारियों से ग्रस्त रहे हैं।
- ट्रंप के समर्थक भी अब स्वीकार करते हैं कि ये कमियां अब राष्ट्रपति ट्रंप में नज़र आने लगी हैं। पर, अहम् सवाल है, क्या इससे सरकार के निर्णय भी प्रभावित होने लगे हैं? क्योंकि, ट्रंप अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं।

गलत साबित हो चुके दावों को दोहराया या फिर बीते और वर्तमान घटनाक्रमों की समय-सीमा को मिलाते हुए बोलते नज़र आए। एक बयान, जिसने काफी ध्यान खींचा, वह था उनका यह दावा कि जैफ्री एपस्टीन फाइलों से जुड़ा विवाद पिछली सरकारों द्वारा गढ़ा गया था, जबकि एपस्टीन की गिरफ्तारी और मृत्यु ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी। समर्थक ऐसे बयानों को केवल भाषण शैली का हिस्सा बताते हैं, जबकि आलोचकों के अनुसार यह अस्थिरता का बढ़ता हुआ पैटर्न है।

बेचैनी बढ़ने का एक और कारण है, ट्रंप के भतीजे फ्रेड ट्रंप तृतीय की नई किताब ''ऑल इन द फैमिली: द ट्रंप्स एंड हाउ वी गॉट दिस वे।'' हालांकि किताब में ट्रंप तृतीय राष्ट्रपति का कोई डायगनोसिस नहीं करते हैं, लेकिन वे परिवार में उम्र से जुड़ी मानसिक बीमारियों के लंबे इतिहास पर बात करते हैं और यह भी कहते हैं कि उन्हें अपने चाचा की बातचीत के तरीके में ''बदलाव'' दिखाई दे रहा है। वे याद करते हैं कि उनके दादा फ्रेड ट्रंप सीनियर कई वर्षों तक अल्ज़ाइमर रोग से जूझते रहे, और अन्य रिश्तेदारों का भी ज़िक्र करते हैं, जिनको ऐसी ही परेशानियाँ हुईं। ट्रंप तृतीय के अनुसार, यह बदलाव केवल उम्र का मामला नहीं है, ट्रंप अब तक के सबसे उम्रदराज़ राष्ट्रपति हैं, बल्कि उनके सार्वजनिक संदेशों में बढ़ती अनिश्चितता ज़्यादा चिंता का विषय है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत को चावल पर ट्रंप की टैरिफ धमकी की चिंता करने की जरूरत नहीं

ट्रंप की धमकी में कोई दम नहीं है, इसके लिए कुछ अहम दलीलें दी जा सकती हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 दिसंबर। भारत ने 2024 में 170 से अधिक देशों को 20 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक चावल का निर्यात किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जो भारत के बाद आने वाले चार देशों के कुल निर्यात से भी ज्यादा है। अमेरिका भारत के चावल निर्यात का केवल 3 प्रतिशत ही खरीदता है।

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ हालिया धमकी ने एक तरह से हलचल मचा दी है, और अब सभी, किसान से लेकर किराना व्यापारी तक, यह इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या यह विवाद चरम तक पहुंचेगा। इस बार, उन्होंने भारत के बासमती चावल पर निशाना साधा और भारत पर, बिना किसी प्रमाण के, सस्ता चावल अमेरिकी बाज़ार में ''डंप करने'' का आरोप लगाया। एक अनौपचारिक टिप्पणी में, राष्ट्रपति ने इसे ''अनुचित'' व्यापार बताते हुए, अपनी आदत के अनुसार, इसे दंडित करने के लिए टैरिफ की धमकी दी।

यह धमकी वाइट हाउस में अमेरिकी किसानों और सांसदों के साथ एक बैठक के दौरान दी गई। दरअसल, यह एक खास किस्म का राजनीतिक ड्रामा है, जिसमें ट्रंप का कोई मुकाबला नहीं है। पाठकों को बता दें कि बैठक में एक नाराज़ किसान ने भारत और अन्य कुछ चावल निर्यातक देशों से सस्ते आयातों की बात कही। ट्रंप ने इस मौके का फायदा उठाया और शिकायत करने वाले किसान को आश्वासन दिया कि वे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बड़बोले अंदाज़ में कहा कि टैरिफ, समस्या का समाधान दो मिनट में कर सकता है।

- पहला तर्क यह है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। निर्यातकों की लिस्ट में भारत के बाद जो चार देश आते हैं, उनका कुल चावल निर्यात भी भारत के निर्यात से कम है, और भारत जितना चावल निर्यात करता है, उसका मात्र तीन प्रतिशत ही अमेरिका को भेजा जाता है।
- दूसरी दलील यह है कि अमेरिका के पास भारत के बासमती चावल का कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका में बासमती चावल उगाया नहीं जा सकता है, इस प्रकार अमेरिकन चावल से भारत के बासमती का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी तथा पर्शियन-अरब प्रवासी बासमती चावल ही पसंद करते हैं।

वर्ष 2025 में, अमेरिका को भारत के चावल निर्यात का मूल्य लगभग 392 मिलियन डॉलर था, जो भारत के कुल चावल निर्यात का लगभग मात्र 3 प्रतिशत था। इसमें से अधिकांश बासमती चावल है, जो लंबे दाने वाला सुगंधित चावल होता है तथा जिसे अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी और फारसी-अरब दुनिया के अप्रवासी बहुत पसंद करते हैं।

अमेरिकी किसान बासमती नहीं उगाते हैं। वे उगा भी नहीं सकते। इसके लिए मिट्टी में विभिन्न तथा अलग किस्म के खनिजों की जरूरत होती है और दाने को पनपने के लिए हिमालय की हवा की आवश्यकता होती है। अमेरिका लंबे और मध्यम लम्बाई वाले चावलों का उत्पादन करता है, जो लुइसियाना, अर्कांसस और कैलिफोर्निया में उगते हैं। इसलिए यह कहना कि भारत अमेरिकी किसानों को बासमती डंप करके नुकसान पहुंचा रहा है, यह कहने के समान होगा कि इटैलियन ऑलिव ऑयल का तेल सोयाबीन बाज़ार को नष्ट कर रहा है। ये एक-दूसरे का विकल्प बिल्कुल नहीं हैं।

व्यापार कानून में ''डंपिंग'' अपमानजनक नहीं है। यह एक तकनीकी निष्कर्ष है। किसी भी देश को यह जांच करनी चाहिए कि निर्यातक अपनी लागत से कम की कीमत पर माल बेच रहा है या नहीं। इसके अलावा, यह साबित भी करना होता है कि इस बिक्री से घरेलू उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। इसमें महीनों की कागजी कार्रवाई, सुनवाई और अपीलें शामिल होती हैं। राष्ट्रपति को यह बताने की हिम्मत कौन करे कि चावल जितना सरल है, यह जटिल और लंबी प्रक्रिया नौकरशाही की प्रक्रिया उतनी ही जटिल है, और अगर बिना प्रमाण के शुल्क बढ़ा दिए जाते हैं, तो भारत के पास इस कदम को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) में चुनौती देने का विकल्प हमेशा रहेगा, चाहे इन दिनों वह अमेरिका के सामने कितना भी विनम्र एवं आत्मसमर्पित क्यों न हो गया हो। भारत ने पहले भी ऐसा किया है और कई मामलों में जीत हासिल की है।लेकिन ट्रंप, शुल्कों का इस्तेमाल एक जादू की छड़ी की तरह करते हैं। वे इसे घुमाते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुनिया डर जाएगी। कानूनी आवश्यकताओं का कोई उल्लेख नहीं, उचित एवं जरूरी प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं, और इस बात का उल्लेख भी नहीं कि अमेरिका ने कुछ उत्पादों से शुल्क हटा लिए, क्योंकि वे अमेरिकी घरों को भी उतना ही नुकसान पहुंचा रहे थे, जितना विदेशी निर्यातकों को।

यदि अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय चावल पर शुल्क और बढ़ाते हैं, तो इसका प्रभाव असमान होगा। अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए, खासकर उन आप्रवासी परिवारों के लिए, जो रोजाना बासमती का उपयोग करते हैं, कीमत बढ़ेगी। भारतीय से लेकर फारसी रेस्तरां तक, सभी पर दबाव पड़ेगा।

खुदरा विक्रेताओं, जो आयातित सुगंधित चावल पर निर्भर हैं, के पास कम विकल्प होंगे। कुछ खरीदार थाई जैस्मिन चावल खरीदने लगेंगे या अन्य सस्ते ग्रेड्स पर जाएंगे, लेकिन उनका कुल बिल बढ़ेगा। अमेरिकी किसानों के लिए, यह कदम सुरक्षा का अहसास करवा सकता है, लेकिन यह संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। अमेरिका चावल की घरेलू किस्में बासमती की जगह नहीं ले सकतीं। टैरिफ से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई लाभ होगा भी, तो वह केवल भावनात्मक होगा, आर्थिक नहीं।